10

अध्याय

उद्योग: मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य

वित्त वर्ष 2024 में औद्योगिक विकास में तेजी आई, जिसमें विनिर्माण और निर्माण सबसे आगे रहे। वित्त वर्ष 2024 में स्थिर कीमतों पर औद्योगिक जीवीए कोविड-पूर्व वित्त वर्ष 20 के स्तर से 25 प्रतिशत अधिक रहा, जो व्यापक आधार पर सुधार और समेकन की पुष्टि करता है। इसे अधिक ऋण उठाव, बुनियादी ढाँचा-उन्मुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निर्माण पर जोर और एक सहायक नीति ढाँचे द्वारा सहायता प्रदान किया गया।

पिछले दशक में, भारत के विनिर्माण परिदृश्य की क्षेत्रीय संरचना में काफी बदलाव हुए हैं। ऑटोमोबाइल, लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कुछ उपभोक्ता-उन्मुख उद्योगों ने उत्पादन हिस्सेदारी में बड़ी बढ़त हासिल की है और मशीनरी, रसायन, गैर-धातु खनिज, और रबर और प्लास्टिक उत्पादों जैसे उत्पादन-उन्मुख क्षेत्रों में भी हिस्सेदारी बढ़ी है, जिससे विकास की गतिशीलता संतुलित हुई है। इसी समय, पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़ा, पेय और तंबाकू जैसे क्षेत्रों में उनके उत्पादन हिस्सेदारी में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई है।

विकास की ओर अग्रसर होते हुए, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को अधिक दक्षता, कौशल और गतिशीलता प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों को बढ़ावा देने से औद्योगिक विस्तार को अधिक संतुलन मिलेगा। अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना, छोटे निर्माताओं का अधिक औपचारिकीकरण, उनकी आपूर्ति श्रृंखला की अड़चनों को दूर करना, बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना और वित्तीय सहायता तक पहुंच में सुधार करना भी औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ में और कमी से उनकी विकास संभावनाओं में काफी सुधार होगा।

खपत और निवेश के कारण घरेलू मांग की स्थिति मजबूत है और निकट भविष्य में औद्योगिक उत्पादन के सुचारू विस्तार के लिए अनुकूल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापार अपेक्षाओं और औद्योगिक दृष्टिकोण पर किए गए एक दूरदर्शी सर्वेक्षण में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, अनिश्चित वैश्विक मांग की स्थिति और प्रमुख इनपुट की कीमतों के मामले में प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसके लिए भारत आयात पर निर्भर है।

परिचय

10.1 वित्त वर्ष 24 में 8.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि 9.5 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि से प्रेरित थी[1]। उद्योग के चार उप-क्षेत्रों में से, विनिर्माण और निर्माण ने दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल की, जबकि खनन और उत्खनन तथा बिजली और जल आपूर्ति ने भी वित्त वर्ष 24 में मजबूत सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। यह औद्योगिक उत्पादन के व्यापक-आधार वृद्धि को दर्शाता है। विनिर्माण के लिए एचएसबीसी इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) भी वित्त वर्ष 24 के सभी महीनों में लगातार 50 के सीमा मूल्य से ऊपर रहा, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर विस्तार और स्थिरता का संकेत देता है।

10.2 वित्त वर्ष 23 में वर्तमान मूल्य के कुल सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण का हिस्सा 14.3 प्रतिशत था। हालांकि, आउटपुट शेयर 35.2 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पिछड़े और आगे के संबंध हैं जो इसके

1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 30 मई 2024 को जारी जीडीपी के अनंतिम अनुमानों के अनुसार। यह फरवरी 2024 में जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित 9 प्रतिशत औद्योगिक विकास से अधिक है, जो वित्त वर्ष 24 के उत्तरार्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन के प्रत्याशित विस्तार से अधिक तेज होने का संकेत देता है।

मूल्य-वर्धित हिस्से में पूरी तरह से शामिल नहीं हैं। देश में कुल उत्पादन मूल्य का लगभग 47.5 प्रतिशत उत्पादक गतिविधियों (अंतर-उद्योग उपभोग)[2] में इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। विनिर्माण गतिविधियां अंतर-उद्योग खपत का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, तथा साथ ही, ये सभी उत्पादक गतिविधियों (कृषि, उद्योग और सेवाएं) में प्रयुक्त इनपुट का लगभग 50 प्रतिशत आपूर्ति करती हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 30 मई 2024 को जारी जीडीपी के अनंतिम अनुमानों के अनुसार। यह फरवरी 2024 में जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित 9 प्रतिशत औद्योगिक विकास से अधिक है, जो वित्त वर्ष 24 के उत्तरार्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन के प्रत्याशित विस्तार से अधिक तेज होने का संकेत देता है।

चार्ट X.1: कुल जीवीए में उद्योग और उसके घटकों का हिस्सा (स्थिर मूल्य में)

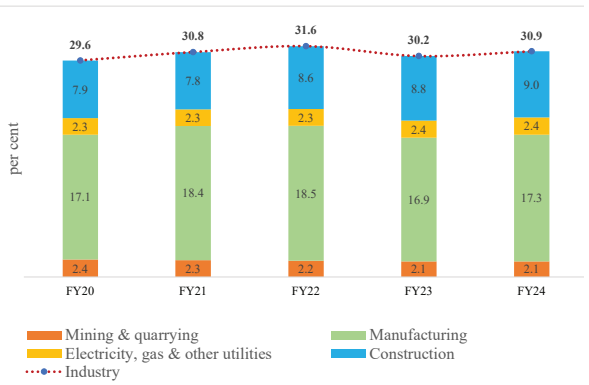

चार्ट X.2: उद्योगों और उसके घटकों की वार्षिक वृद्धि (स्थिर मूल्यों में)

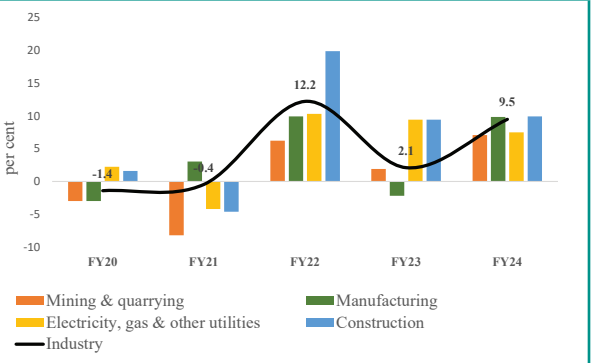

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 (विवरण 8.6.1 और 8.6.2) पर आधारित सर्वेक्षण गणना, एमओएसपीआई

चार्ट X.3: भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक

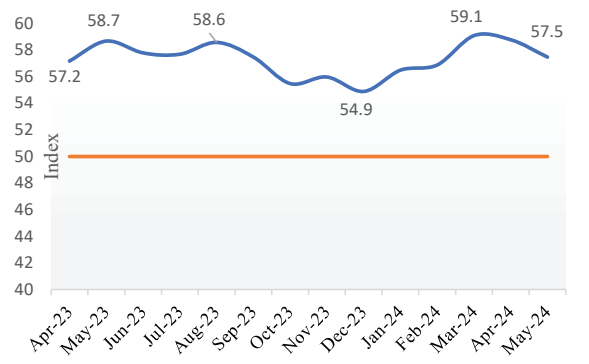

स्रोत: आईएचएस मार्किट
नोट: 'इसमें विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और परिवहन उपकरण शामिल नहीं हैं

चार्ट X.4: स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण जीवीए के घटकों में औसत वार्षिक वृद्धि (वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 तक)

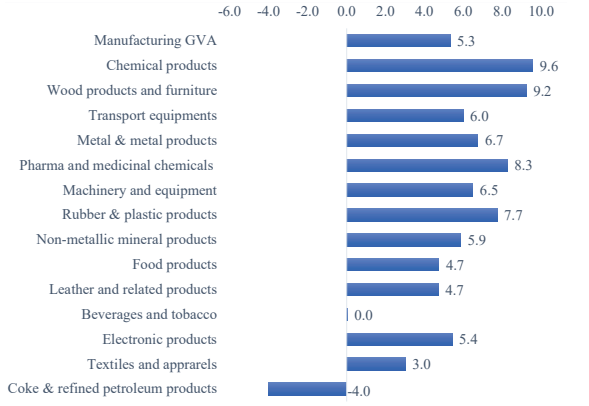

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 (विवरण 8.6.1 और 8.6.2) पर आधारित सर्वेक्षण गणना, एमओएसपीआई

10.3 महामारी और उसके परिणामस्वरूप विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं की हानि के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में 5.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। पिछले दशक में विनिर्माण उप-क्षेत्रों ने उत्पादन हिस्सेदारी में काफी पुनर्निर्धारण देखा। पिछले दशक में विनिर्माण वृद्धि के उत्प्रेरकों में रसायन, लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर,

2 वित्त वर्ष 20 के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं के अनुसार।

परिवहन उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी और उपकरण शामिल थे। उनमें से, इस्पात, मशीनरी और उपकरण, लकड़ी के उत्पाद और परिवहन उपकरण, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण पर जोर देता है।

चार्ट X.5: वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 23 के बीच कुल जीवीए में निर्मित उत्पादों के जीवीए के हिस्से में परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर)

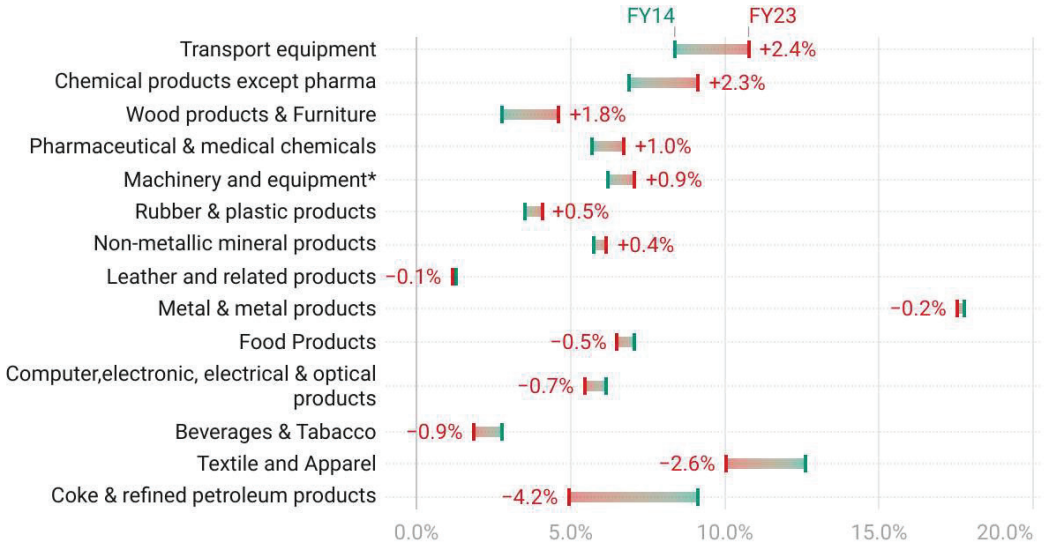

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024 (विवरण 8.6.1 और 8.6.2) पर आधारित सर्वेक्षण गणना, MoSPI
नोट: 'इसमें विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और परिवहन उपकरण शामिल नहीं हैं

10.4 भारत का औद्योगिकीकरण भौतिक अवसंरचना और रसद की कमी के साथ-साथ क्षमता निर्माण और विस्तार पर हस्तक्षेप करने वाली और बोझिल लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के कारण रुका हुआ था। इसके अलावा, विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित था। इनमें से अधिकांश प्रतिबंध अब हटा दिए गए हैं, और भौतिक अवसंरचना का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ने कई वस्तुओं के लिए एकल बाजार बनाया है, जिससे बड़े पैमाने पर विनिर्माण संभव हो पाया है। हालांकि, भारत को अपने विनिर्माण आधार को बढ़ाने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक नीति को प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कार्रवाई मुख्य रूप से विनियमन में निहित है। निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक सोचना चाहिए और अनुसंधान एवं विकास खर्च के माध्यम से गुणवत्ता में निवेश करना चाहिए। ये पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक शर्तें हैं। विनिर्माण में अभी भी कम और अर्ध-कुशल नौकरियां पैदा करने और लोगों के करीब विकास लाने की क्षमता है। भारत को इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

10.5 अध्याय के शेष भाग निम्नलिखित तरीके से व्यवस्थित हैं। अगला भाग विभिन्न औद्योगिक खंडों, जैसे कि प्रमुख औद्योगिक मध्यवर्ती और उपभोक्ता-उन्मुख उद्योगों में प्रगति, चुनौतियों और नीतिगत पहलों की जांच करता है[3]। इसके बाद उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), औद्योगिक वित्तपोषण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार जैसे क्रॉस-कटिंग विषयों पर संक्षिप्त चर्चा की गई है। अंतिम सत्र में चर्चा का समापन होता है तथा आगे का रास्ता बताया जाता है।

3 उर्वरक को कृषि और खाद्य प्रबंधन पर अध्याय 8 में शामिल किया गया है

प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन और संबंधित मुद्दे

प्रमुख औद्योगिक घटक

सीमेंट: भविष्य का निर्माण

10.6 सीमेंट उद्योग भारत में निर्माण क्षेत्र में लगभग 11 प्रतिशत इनपुट लागत का योगदान देता है[4]। 1991 में डी-लाइसेंसिंग के बाद से, सीमेंट उद्योग ने क्षमता और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी दोनों में उल्लेखनीय प्रगति की है, इतनी कि भारत चीन[5] के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है।

10.7 भारतीय सीमेंट उद्योग में 159 एकीकृत बड़े सीमेंट संयंत्र, 120 ग्राइंडिंग इकाइयाँ और 62 मिनी सीमेंट संयंत्र शामिल हैं। भारत में सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता लगभग 622 मिलियन टन है, जिसमें वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन लगभग 427 मिलियन टन है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थित हैं। सीमेंट उद्योग का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में केंद्रित है।

10.8 उद्योग के पास घरेलू सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है; वित्त वर्ष 23 में आयातित सीमेंट की मात्रा कुल घरेलू सीमेंट उत्पादन का लगभग 0.2 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2019 तक क्लिंकर और अन्य सीमेंट का निर्यात बढ़ा और फिर वैश्विक मांग में कमी और अन्य देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अन्य हाइड्रोलिक सीमेंट को छोड़कर इसमें गिरावट शुरू हो गई। वित्त वर्ष 23 में भारत ने केवल नाम मात्र में क्लिंकर का निर्यात किया।

चार्ट X.6: सीमेंट उद्योग की स्थापित क्षमता, उत्पादन क्षमता उपयोग

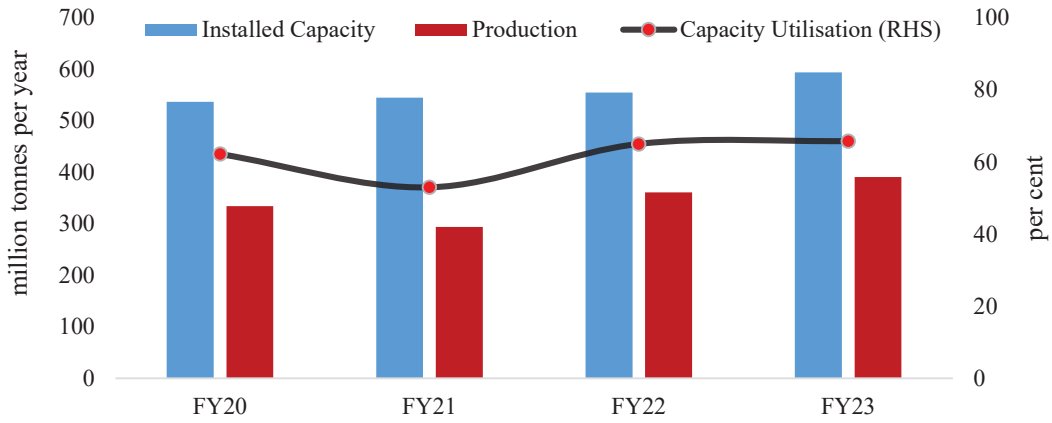

स्रोत: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)

10.9 उद्योग ने हाल के वर्षों में लगभग 60-65 प्रतिशत की क्षमता उपयोग दर बनाए रखी है। रिपोर्टों में यह भी उम्मीद जताई गई है कि 2024-2030 के दौरान सीमेंट की वैश्विक मांग स्थिर रहने की संभावना है, जिसमें केवल भारत, अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका से ही मांग में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी सीमेंट उद्योग में सकल मार्जिन वैश्विक स्तर पर मजबूत रहने की संभावना है, जिसे उच्च कीमतों और कम ईंधन लागतों से मदद मिलेगी[6]।

10.10 भारत में घरेलू सीमेंट की खपत लगभग 260 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक औसत 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। पिछले दस वर्षों में क्लिंकर का आयात बढ़ा है। हालाँकि, आयात की मात्रा अभी भी कम है

4 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2023-24, विवरण 8.8: निर्माण से उत्पादन और मूल्य वर्धन,

5 डीपीआईआईटी

6 ग्लोबल सीमेंट इंडस्ट्री आउटलुक: रुझान और पूर्वानुमान। लिंक: https://www.worldcementassociation.org/blog/news/global-cement-industry-outlook-trends-and-forecasts.

10.11 सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास और शहरीकरण से प्रेरित है। राजमार्गों, रेलवे, आवास योजनाओं और स्मार्ट शहरों जैसी मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार का ध्यान सीमेंट की मांग को काफी बढ़ावा देगा। ग्रामीण विकास पर जोर और औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्माण में निवेश में वृद्धि से विकास की संभावनाओं को समर्थन मिलता है।

10.12 वैश्विक स्तर पर, सीमेंट क्षेत्र कुल मानवजनित उत्सर्जन का लगभग 7 प्रतिशत उत्पन्न करता है। भारतीय सीमेंट उद्योग इस मुद्दे पर काम कर रहा है। अनुमान है कि 2023 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 0.56 टन CO_2 प्रति टन सीमेंट तक कम हो जाएगा। जैसा कि सीमेंट उद्योग प्रौद्योगिकी रोडमैप में अनुमान लगाया गया है, 2050 तक CO_2 उत्सर्जन को 0.35 टन CO_2 प्रति टन सीमेंट तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।[7]

इस्पात क्षेत्र विकास पथ पर

10.13 निर्माण क्षेत्र में सभी इनपुट में लोहा और इस्पात का योगदान लगभग 47 प्रतिशत है[8]। यह मशीनरी और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में भी कार्य करता है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान इस्पात क्षेत्र ने उत्पादन और खपत का उच्चतम स्तर हासिल किया।

10.14 भारत पिछले दशक में तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक बन गया है, जिसमें निर्यात वृद्धि आयात से अधिक हो गई है। वित्त वर्ष 24 में, भारत ने Q1 में शुद्ध निर्यातक के रूप में शुरुआत की। हालाँकि, वित्त वर्ष 24 की दूसरी और तीसरी तिमाही में, यह शुद्ध आयातक बन गया। यह मुख्य रूप से तैयार स्टील की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के बीच मूल्य अंतर से प्रेरित था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमतों के कारण निर्यात के लिए लाभ मार्जिन कम हो गया और आयात अधिक किफायती हो गया, जिससे स्टील में व्यापार संतुलन प्रभावित हुआ। हालाँकि, इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल, कोकिंग कोयले पर आयात निर्भरता वित्त वर्ष 2023 में 56.1 मीट्रिक टन से घटकर वित्त वर्ष 24 में 58.1 मीट्रिक टन हो गई।

10.15 जैसे-जैसे दुनिया निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, हरित इस्पात इस्पात उद्योग के भविष्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत के इस्पात क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत[9] है, जिसकी उत्सर्जन तीव्रता 2.5 टन CO_2 प्रति टन कच्चे इस्पात की है, जबकि वैश्विक औसत 1.9 टन CO_2 प्रति टन कच्चे इस्पात की है।

चार्ट X.7: तैयार इस्पात की औसत वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

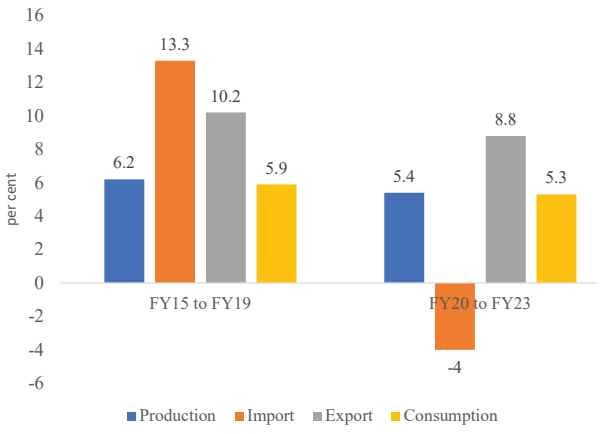

चार्ट X.8: वित्त वर्ष 24 में तैयार इस्पात की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)

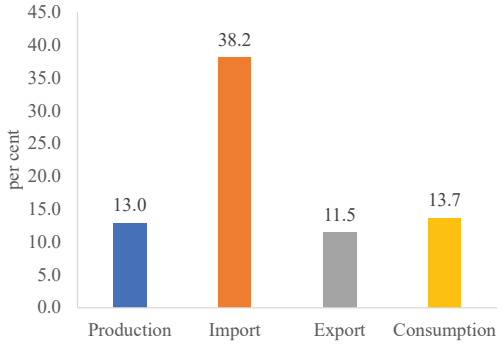

स्रोत: इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

7 सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद, 2018

8 राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2023-24, विवरण 8.8: निर्माण से उत्पादन और मूल्य वर्धन, एमओएसपीआई I

9 इस्पात मंत्रालय

चार्ट X.9: भारत पिछले 5 वर्षों में से 4 वर्षों में तैयार इस्पात का निवल निर्यातक रहा

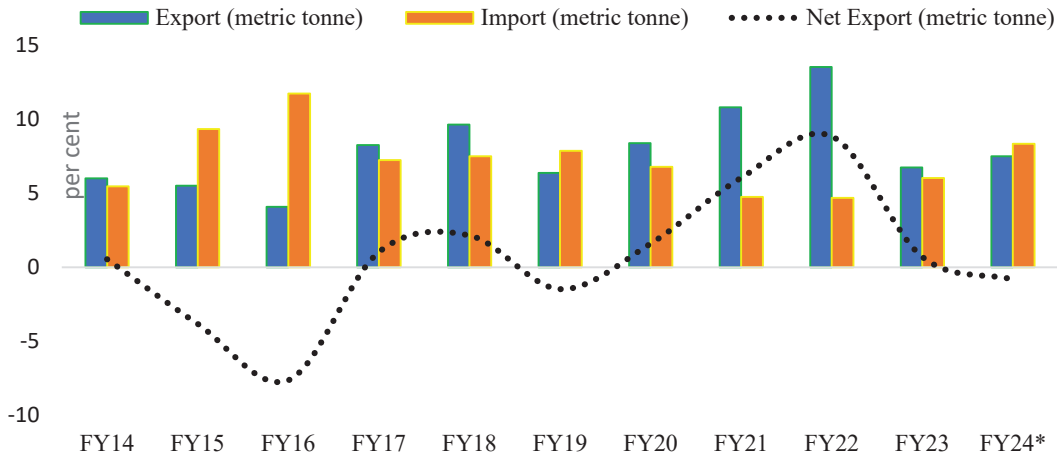

स्रोत: इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना
नोट: 'अनंतिम

बॉक्स X.1: इस्पात क्षेत्र की पहल

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अक्टूबर 2023 में बस्तर जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना की, जो भारत की इस्पात उत्पादन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड परियोजना से उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगा और भारत को वैश्विक इस्पात बाजार में एक प्रमुख किरदार के रूप में स्थापित करेगा। संयंत्र को फ्लैट स्टील उत्पादों की एक श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्त वर्ष 24 में, संयंत्र ने 4.93 लाख टन हॉट-रोल्डकॉइल का उत्पादन किया। स्टील सीपीएसई के बीच, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 24 में हॉटमेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य इस्पात का अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन हासिल किया।

वर्ष 2021 में स्वीकृत स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना ने 24 मई तक ₹15,519 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। 17.03.2023 को, इस्पात मंत्रालय ने 57 आवेदनों वाली 27 चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस योजना से 24,780 हजार टन की क्षमता वृद्धि के साथ कुल ₹29,531 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा।

स्रोत: इस्पात मंत्रालय

कोयला: बाहरी निर्भरता कम करना

10.16 भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक है। कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है। पिछले पाँच वर्षों में कोयले के उत्पादन में तेजी आई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। वित्त वर्ष 24 में, भारत ने 997.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, 261 मीट्रिक टन का आयात किया और 1233.86[10] मीट्रिक टन की खपत की। पिछले दशक में कोयले के घरेलू उत्पादन और खपत के अनुपात में धीरे-धीरे सुधार हुआ क्योंकि उत्पादन में वृद्धि ने खपत में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया

10 कोयला मंत्रालय

चार्ट X.10: घरेलू खपत के प्रतिशत के रूप में कोयला उत्पादन

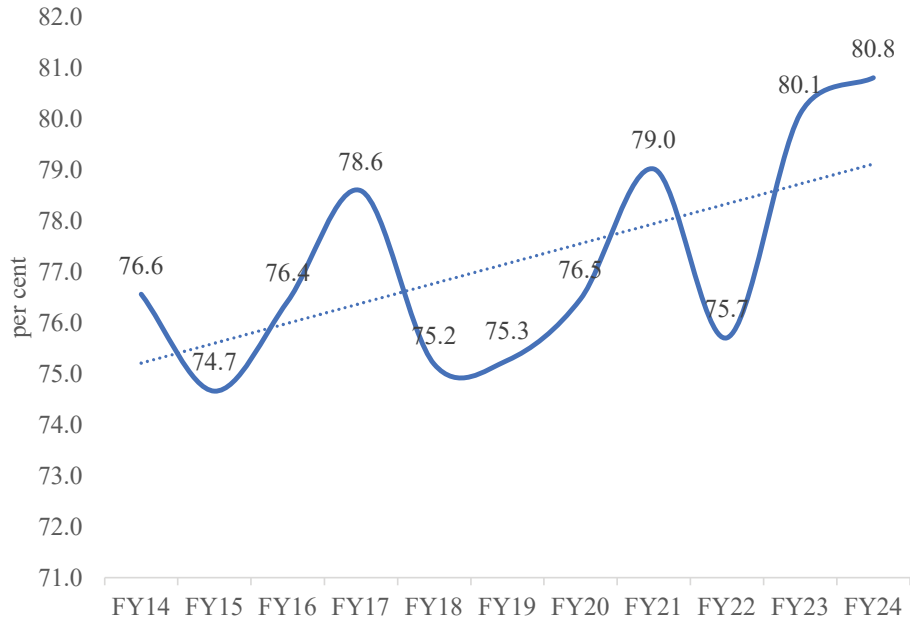

स्रोत: कोयला मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

तालिका X.1: कोयले के उत्पादन, खपत और आयात में वृद्धि (सीएजीआर प्रतिशत में)

वर्ष	उत्पादन	खपत	आयात
वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 19	5.2	5.6	7.1
वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 24	6.5	5.0	2.1
वित्त वर्ष 24 (वर्ष दर वर्ष)	11.7	10.7	9.8

स्रोत: कोयला मंत्रालय

बॉक्स X.2: कोयला क्षेत्र में हालिया पहल, चुनौतियां और अवसर

हालिया पहल	चुनौतियाँ, अवसर और विकल्प
• सरकार ने आयात कम करने के लिए 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा है। • कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 2023-24 के दौरान 8500 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक योजना शुरू की गई है। • कोयला निकासी के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत और लागत प्रभावी रसद विकसित करने के लिए फरवरी 2024 में एकीकृत कोयला रसद नीति और योजना शुरू की गई। • मई 2023 में संशोधित कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया।	• स्वदेशी निर्माताओं से आधुनिक खनन उपकरणों की सीमित उपलब्धता के कारण तकनीकी कठिनाइयाँ। • खनन परियोजनाओं के समय पर विकास के लिए वानिकी और पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कब्जे को प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक जटिलताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। • वैश्विक पर्यावरण सक्रियता के बीच स्थायी समाधानों की आवश्यकता • चुनौतियों को कम करने के लिए, उद्योग उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) 2025-26 तक बिजली खनन कार्यों के लिए 3,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का उपक्रम कर रही है। 2023-24 के दौरान, दिसंबर 2023 तक सौर प्रतिष्ठानों से कुल 8.60 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- सीआईएल धीरे-धीरे उच्च क्षमता वाली कोयला निकासी प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, जो अपनी 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत कोयला हैंडलिंग प्लांट/साइलो स्थापित करके इसे अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है।
- यह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला परिवहन और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं में तकनीकी परिवर्तन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- सीआईएल भारत और विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण का प्रयास कर रहा है।
- थर्मल कोयले की पर्याप्त घरेलू आपूर्ति के बावजूद, आयात का केवल प्रतिस्थापन योग्य हिस्सा ही बदला जा सकता है। कोकिंग कोल की बढ़ती मांग कोकिंग कोल के आयात को बढ़ाएगी। 'कोकिंग कोल मिशन' के तहत आयातित कोयले के साथ मिश्रण के लिए कोकिंग कोयला के लाभ को बढ़ाने की जरूरत है।
- कोयले का उपयोग हरित ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है, जैसे कोल माइन मीथेन (सीएमएम), कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल टू लिक्विड और कोल टू मेथनॉल। सीएमएम और सीबीएम का उत्तरोत्तर उपयोग किया जाना चाहिए।

स्रोत: कोयला मंत्रालय

प्रमुख उपभोक्ता-उन्मुख उद्योग

फार्मास्यूटिकल्स: बढ़ती और वैश्विक उपस्थिति

10.17 भारत का दवा बाजार वर्तमान में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और यह मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। जेनेरिक दवाओं, सक्रिय दवा सामग्री, बल्क ड्रग्स, ओवर-द-काउंटर दवाओं, टीकों, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर को कवर करने वाले बेहद विविध उत्पाद आधार के साथ, भारतीय दवा उद्योग की वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति है। इसे 'दुनिया की फार्मेसी' कहा जाता है, जो 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 जेनेरिक ब्रांड प्रदान करती है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात का 20 प्रतिशत है। आश्चर्य की बात नहीं है कि शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से आठ भारत में स्थित हैं।

10.18 भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में गुणवत्ता अनुपालन की उच्च दर है, जिसमें 703[11] यूएस एफडीए-अनुमोदित सुविधाएं (अप्रैल 2023 तक), 386[12] यूरोपीय जीएमपी-अनुपालक संयंत्र (नवंबर 2022 तक) और 2418[13] डब्ल्यूएचओ-जीएमपी-अनुमोदित संयंत्र हैं। विनियामक ढांचे को और मजबूत करने के लिए, दिसंबर 2023 में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से संबंधित अनुसूची-एम के तहत संशोधित फार्मा विनिर्माण नियमों को अधिसूचित किया गया, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है जो गुणवत्ता की रक्षा करती है और मौजूदा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाती है।[14]

11 फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, हैंडबुक, 2023 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जोड: https://pharmexcil.com/uploads/files/Hand_Book_Design.pdf

12 फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, हैंडबुक, 2023। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। लिंक: https://pharmexcil.com/uploads/files/Hand_Book_Design.pdf

13 https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/system/modules/CDSCO.WEB/elements/industry_download.jsp\num_id¾MTcyNQ¾¾

14 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2023 https://pharmadocx.com/wp- content/uploads/2024/01/Notified-Schedule-M-dt-28.12.2023-1.pdf

चार्ट X.11: वित्त वर्ष 24 में फार्मा क्षेत्र का कारोबार, निर्यात और आयात

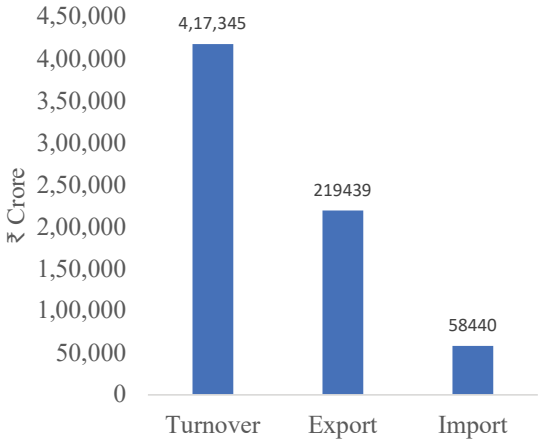

चार्ट X.12: फार्मा क्षेत्र में घरेलू कारोबार वृद्धि

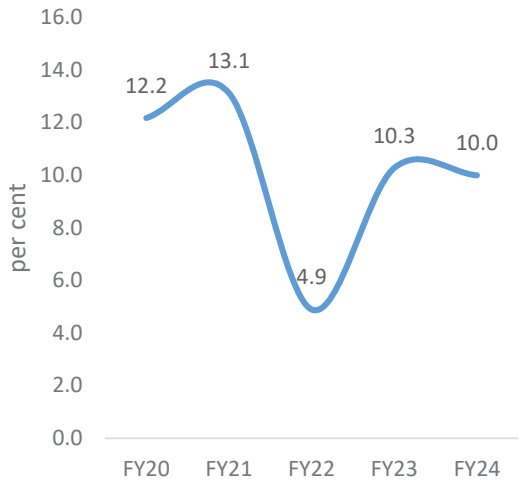

स्रोत: फार्मास्युटिकल विभाग

10.19. भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग पारंपरिक रूप से एक देश से एपीआइ आयात पर निर्भर रहा है। बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजनाओं ने बल्क ड्रग्स के आयात को स्थिर करने और हमारी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में सुधार करने में मदद की है। इस योजना के तहत, पेनिसिलिन जी और क्लैवुलैनिक एसिड जैसे एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के माध्यम से किण्वन-आधारित विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत किया गया। वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 24 के बीच बल्क ड्रग्स के आयात का सीएजीआर 2.3 प्रतिशत था, जबकि उनके निर्यात में सीएजीआर 5.9 प्रतिशत था। भारत बल्क ड्रग्स का शुद्ध निर्यातक बन गया है। वित्त वर्ष 24 के दौरान, बल्क ड्रग्स के निर्यात और आयात का मूल्य क्रमशः 39,632 करोड़ और 37,722 करोड़ था।

10.20 चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना सकारात्मक प्रोत्साहन प्रदान करने लगी है, जैसा कि चिकित्सा उपकरणों के निर्यात और आयात के बीच कम होते अंतर में परिलक्षित होता है। देश में सीटी-स्कैन मशीन, लीनियर एक्सेलेरेटर (एलआईएनएसी), रोटेशनल कोबाल्ट मशीन, सी-आर्म, एमआरआई आदि जैसे कई चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है।[15]

बॉक्स X.3: फार्मा क्षेत्र की हालिया पहल, चुनौतियां और दृष्टिकोण

आत्मनिर्भरता का अनुसरण	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि	चुनौतियां और दृष्टिकोण
• इसका उद्देश्य बड़े निवेश को आकर्षित करके और महत्वपूर्ण एपीआई पर आयात निर्भरता को कम करके पहचाने गए केएसएम, डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। • थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत 3938.6 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।	• इसका उद्देश्य सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। • प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए खुले हैं। अब तक सभी जिलों को कवर करते हुए 12500 से अधिक पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं।	• भारत किण्वन के माध्यम से निर्मित कई एंटीबायोटिक एपीआई के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत की आयात निर्भरता काफी हद तक आयात की तुलना में घरेलू एपीआई विनिर्माण में लागत प्रभावी विकल्पों की कमी के कारण है। हाल के वर्षों में घरेलू बुनियादी ढांचे और अनुसंधान एवं विकास

15 पीआईबी जारी 17 जनवरी 2024 लिंक: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1996964

• बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इससे बल्क ड्रग की विनिर्माण लागत में कमी आएगी और भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और दवा सुरक्षा में सुधार होगा।	• इसने किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवा कर आम जनता और गरीबों पर प्रभाव डाला है। • वित्त वर्ष 23-24 में, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने ₹1470 करोड़ मूल्य की जन औषधि दवाएं बेचीं, जिससे लगभग ₹7350 करोड़ की बचत हुई। • इस योजना से विशेष रूप से पुरानी बीमारियों के लिए दवाओं पर अधिक बचत हो रही है। औसतन, प्रतिदिन 10-12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों पर आते हैं।	क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं (बॉक्स X.10)। • पिछले 5-6 दशकों में लगातार नवाचार के कारण निर्यात में वृद्धि हुई है। बायोफार्मास्युटिकल्स विनिर्माण में क्षमताओं को बढ़ाकर निर्यात वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। • फार्मा उद्योग के 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। • फार्मा में विकास के अगले चरण के लिए कौशल उन्नति, नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना की आवश्यकता है।

स्रोत: फार्मास्युटिकल विभाग

बॉक्स X.4: फार्मा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने और पुनर्कल्पित करने की आवश्यकता

दुनिया भर में फार्मास्युटिकल उद्योग को इनोवेटर या जेनेरिक निर्माता में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, 'इनोवेटर' फर्म दुनिया में बीमारियों के लिए नई दवाएं या उपचार लाने के लिए व्यापक शोध करती हैं। समय और संसाधनों की सीमा और इस प्रक्रिया में शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए, ऐसी दवाओं की कीमतें आमतौर पर बहुत अधिक होती हैं। ऐसी कंपनियाँ इन नई दवाओं के लिए उनके स्वामित्व वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से बनाए गए एकाधिकार पर फलती-फूलती हैं। हाल के वर्षों में, बड़ी इनोवेटर फार्मा कंपनियों ने छोटी, अधिक सक्रिय अनुसंधान-उन्मुख फर्मों में निवेश करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाया है। 2021 और 2023 के बीच छोटी बायो-टेक फर्मों में 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ।[16]

फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की ताकत मौजूदा पेटेंट रहित दवाओं का लागत प्रभावी और कुशल उत्पादक होने में निहित है- जिसे जेनेरिक उद्योग भी कहा जाता है। फिर भी शोध और विकास मूल दवा की लागत के एक अंश पर पेटेंट से मुक्त होने के बाद उन्हीं दवाओं का उत्पादन करने की कुंजी है। वे प्रतिस्पर्धा पर पनपते हैं। दुनिया को नवोन्मेषकों और उन लोगों की जरूरत है जो उचित मूल्य पर दवाएँ उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें सामाजिक लाभ बढ़ाने में बाद वाले की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, उद्योग की ताकत नवोन्मेषकों और जेनेरिक उत्पादकों के विविध संयोजन में निहित है।

जैसे-जैसे हम विकसित भारत के विजन को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं, नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। भारत में दवाओं और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व्यय वित्त वर्ष 20 और वित्त वर्ष 21 में बिक्री कारोबार का औसतन लगभग 5 प्रतिशत रहा।[17] अनसुलझे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से नई दवाओं के विकास से आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच की व्यापकता और गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा।

रिपोर्ट "भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्रीय नवाचार प्रणाली"[18] निम्नलिखित की आवश्यकता को रेखांकित करती है:

i) उद्योग जगत के प्रवर्तकों के बीच संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी के बजाय रणनीतिक रूप से अधिक सहयोगात्मक बनाना है।

16 द इकोनॉमिस्ट, अप्रैल 30 2024, क्या बायोटेक स्टार्टअप एली लिली और नोवो नॉर्डिस्क को आगे बढ़ा सकते हैं?
पहुँच के लिए लिंक: (https://www.economist.com/business/2024/04/30/can-biotech-startups-upstage-eli-lilly-and-novo-nordisk)

17 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुसंधान एवं विकास व्यय; और फार्मास्यूटिकल्स विभाग से बिक्री कारोबार।

18 https://dst.gov.in/sites/default/files/Indian%20Pharmaceutical%20Sectorial%20System%20of%20Innovation%20%28IPSSI%29%20Report_0.pdf

ii) अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए उद्योग-अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सार्वजनिक ज्ञान-आधारित संस्थानों की बेहतर भागीदारी।

iii) अनुसंधान के क्षेत्रों में बेहतर ज्ञान विनिमय और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान-आधारित संस्थानों विशेष रूप से टियर2 और टियर3 संस्थानों को शामिल करके इनके बीच बातचीत की कठोरता को कम करना।

iv) मानव पूंजी विकास को बेहतर ढंग से उन्मुख करने के लिए ज्ञान-आधारित संस्थानों और उद्योग के बीच सेकंडमेंट और प्लेसमेंट का समर्थन करना।

v) ज्ञान-आधारित संस्थानों और मध्यस्थों, विशेष रूप से उद्योग संघों के बीच संचार चौनलों को मजबूत करना।

vi) विचार-विमर्श से लेकर बाजार तक की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए उद्यम पूंजी और एंजेल निवेशकों से वित्त पोषण के चौनलों को बढ़ाना।

vii) नवाचार के लिए 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निकायों के बीच बेहतर ज्ञान साझा करना, जिससे रणनीतिक क्षेत्रों में अधिक समन्वित संयुक्त अनुसंधान हो सके।

सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने और विकसित करने के लिए कई उपाय किए हैं। यह दवा क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और स्वास्थ्य क्षेत्र सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता में परिलक्षित होता है। हाल ही में शुरू किए गए फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से दवा क्षेत्र में नवाचार की दिशा में बदलाव की उम्मीद है।

कपड़ा उद्योग: चुनौतियों का सामना करना

10.21 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय खातों के अनुसार, परिधान क्षेत्र सहित वस्त्रों ने वित्त वर्ष 23 में ₹3.77 लाख करोड़ का सकल मूल्य वर्धित किया, जो वर्ष के दौरान मौजूदा कीमतों पर विनिर्माण जीवीए का लगभग 10.6 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2013 में इस क्षेत्र की कुल गैर-कॉर्पोरेट विनिर्माण जीवीए में 29.3 प्रतिशत और कॉर्पोरेट विनिर्माण जीवीए में 7.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।

10.22 भारत के पास कपड़ा उद्योग में एक मजबूत एंड-टू-एंड वैल्यू चेन है, जो प्राकृतिक और एमएमएफ फाइबर जैसे कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक फैली हुई है और इसमें परिधान, घरेलू वस्त्र और तकनीकी वस्त्र शामिल हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष पांच निर्यातक देशों में से एक है। वित्त वर्ष 24 में, हस्तशिल्प सहित वस्त्र और परिधान का निर्यात 1 प्रतिशत बढ़कर ₹2.97 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह क्षेत्र विविधतापूर्ण है, जिसमें वित्त वर्ष 24 में कुल निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (41 प्रतिशत) रेडीमेड कपड़ों की है, जिसका निर्यात ₹1.2 लाख करोड़ था, इसके बाद सूती वस्त्र (34 प्रतिशत) और मानव निर्मित वस्त्र (14 प्रतिशत) का स्थान है।

चार्ट X.13: कुल कपड़ा (परिधान सहित) जीवीए में गैर-कॉर्पोरेट जीवीए का हिस्सा

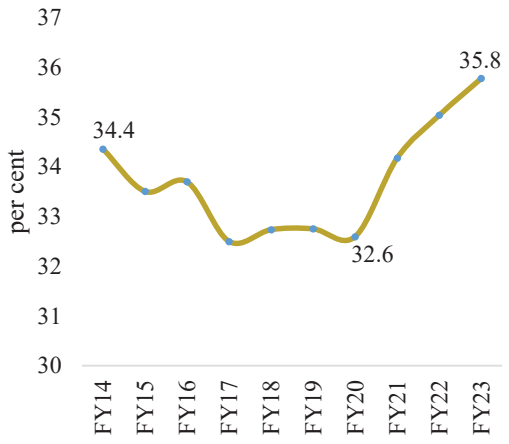

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2024, एमओएसपीआई

चार्ट X.14: वस्त्र उत्पादों का कुल निर्यात

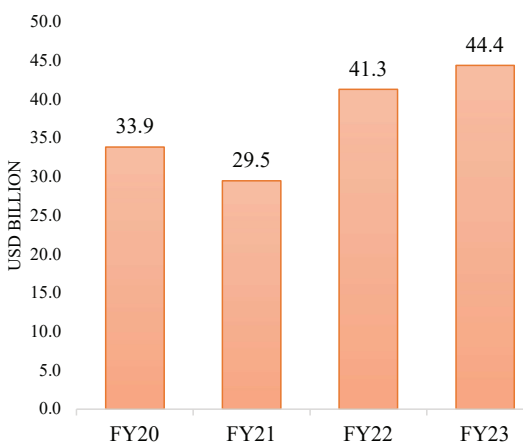

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय

बॉक्स X.5: कपड़ा उद्योग में चुनौतियां और सहायक पहल

उद्योग संदर्भ और चुनौतियाँ	सहायक पहल
• भारत की कपड़ा और परिधान उत्पादन क्षमता का अधिकांश हिस्सा एमएसएमई के कारण है, जो इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, और परिचालन का औसत पैमाना अपेक्षाकृत छोटा है। इस प्रकार, बड़े पैमाने पर आधुनिक विनिर्माण से दक्षता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ सीमित हैं। • भारत के परिधान क्षेत्र की विखंडित प्रकृति, जिसमें कच्चे माल मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से प्राप्त होते हैं, जबकि कताई क्षमताएँ दक्षिणी राज्यों में केंद्रित हैं, उच्च परिवहन लागत और देरी में योगदान देता है। • अन्य कारक, जैसे कि कताई क्षेत्र को छोड़कर आयातित मशीनरी पर भारत की भारी निर्भरता, कुशल जनशक्ति की अपर्याप्त उपलब्धता, तकनीकी अप्रचलन आदि भी महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। • नीति आयोग की सिफारिशों में इस क्षेत्र के लिए एटीयूएफएस जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू मशीन निर्माताओं का समर्थन करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। • प्राथमिकताओं में प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय कपड़ा बुनियादी ढाँचा बनाना भी शामिल है। तकनीकी उन्नयन, स्थिरता और परिपत्रता, गुणवत्ता और मानकों और हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार पर भी ध्यान दिया जाएगा।	• तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 28 तक ₹4,445 करोड़ रुपये के बजट के साथ सात पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। • पार्कों में 1,000 एकड़ का औद्योगिक बुनियादी ढांचा और 'प्लग एंड प्ले' सुविधाएं होंगी। • सभी सात राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, पांच राज्यों में संयुक्त उद्यम और एसपीवी स्थापित किए गए। • सरकार ने मानव निर्मित फाइबर परिधान और कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के लिए पांच वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इससे 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होने और 2.5 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। • वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 के लिए 1,480 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। • इसके चार घटक हैं: अनुसंधान, नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, तथा निर्यात संवर्धन। इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें मार्च 2028 तक का सनसेट क्लॉज है। • अब तक ₹474 करोड़ की 137 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। • वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 के लिए ₹998 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को मंजूरी दी गई है। • वित्त वर्ष 24 में 96 छोटे हथकरघा क्लस्टर स्थापित करने की पहल की गई। नौ मेगा हथकरघा क्लस्टर भी स्थापित किए गए हैं।

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग: भविष्य को सशक्त बनाना

10.23 भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ने 2014 से उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो वित्त वर्ष 22 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमानित 3.7 प्रतिशत है। वहीं, वित्त वर्ष 22 में उद्योग ने भारत के कुल सकल घरेलू

उत्पाद में 4 प्रतिशत का योगदान दिया। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 8.22 लाख करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 23 में निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ हो गया। भारत तेजी से इस क्षेत्र में निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है, और पिछले पांच वर्षों में देश में पर्याप्त विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। कई प्रमुख ब्रांड, विदेशी और घरेलू दोनों ने या तो अपनी खुद की विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं या भारत में काम कर रही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा कंपनियों को विनिर्माण आउटसोर्स किया है।

चार्ट X.15: इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

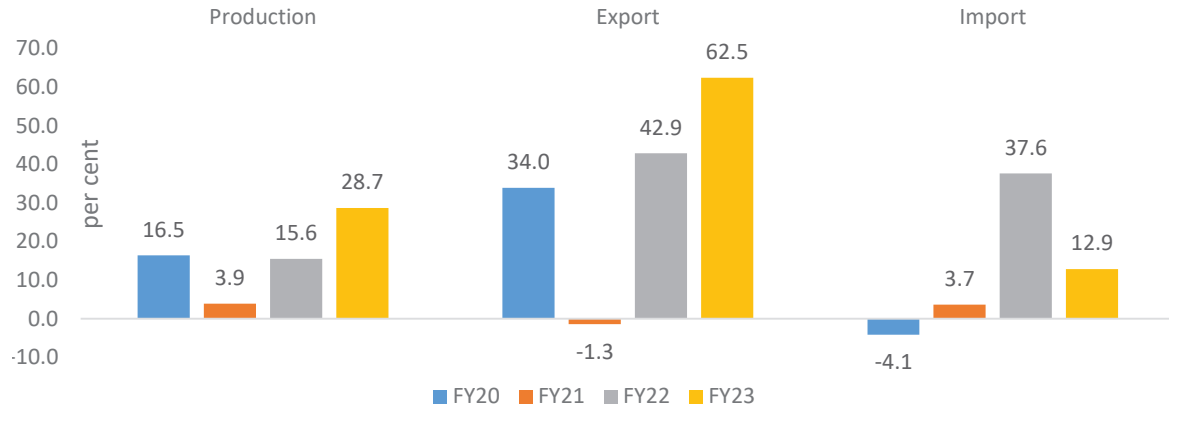

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)

10.24. सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज[19] के शोध से पता चलता है कि भारत ने वित्त वर्ष 2017 से मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए), रोजगार, मजदूरी और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। मोबाइल फोन उत्पादन में डीवीए की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2019 (चरण 1) में औसतन 8.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 2022 (चरण 2) में 22 प्रतिशत हो गई, जो स्थानीय भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। जबकि निर्यात के अनुपात के रूप में डीवीए कम हो सकता है, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भागीदारी से विशाल वैश्विक बाजार के लिए विनिर्माण में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के कारण समग्र मूल्य संवर्धन में वृद्धि होती है। मोबाइल फोन के उत्पादन में प्रत्यक्ष कार्यबल वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2022 के बीच तीन गुना से अधिक हो गया है, जिसका विशेष रूप से महिला ब्लू-कॉलर श्रमिकों को लाभ हुआ है। चरण 1 और चरण 2 के बीच मजदूरी और वेतन में 317 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अध्ययन से पता चलता है कि जीवीसी में निर्बाध भागीदारी के लिए सेवा लिंक लागत को कम करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लेनदेन लागत को कम करने के प्रयासों की आवश्यकता है। यह अन्य क्षेत्रों में सफलता को दोहराने के लिए मध्यवर्ती इनपुट के लिए कम आयात शुल्क सहित एक व्यापक नीति दृष्टिकोण की सिफारिश करता है।

बॉक्स X.6: इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने की पहल

भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण को उच्च प्राथमिकता देती है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' दोनों पहलों का एक प्रमुख पहलू है। इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं: (i) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), (ii) पीएलआई आईटी हार्डवेयर, (iii) इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना, और (iv) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0)। ये योजनाएं देश के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विकास को गति देने में सहायक रही हैं। नतीजतन, वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 223 तक इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के उत्पादन में सीएजीआर 16.19 प्रतिशत रहा, जबकि इसी अवधि में निर्यात में 35.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

19 वीरमणि, सी. (2024 आगामी) ष्वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में पिछड़ी भागीदारी के माध्यम से भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण से लाभष्, विकास अध्ययन केंद्र (सीडीएस), तिरुवनंतपुरम, भारत

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना 2020 में शुरू की गई थी। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक विशिष्ट सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत का पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। मार्च 2024 तक, इस योजना के तहत ₹12,638 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और ₹1758 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई है।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी/ईएमसी 2.0) योजना
➢ मई 2023 में अधिसूचित इस योजना का उद्देश्य बिक्री और निवेश सीमा से जुड़े घटकों और उप-असेंबली के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहरा बनाना है। ➢ यह योजना छह वर्षों के लिए भारत में निर्मित पात्र वस्तुओं की निवल वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 5 प्रतिशत का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना की प्रगति: कुल उत्पादन: ₹3367.63 करोड़ अतिरिक्त निवेश: ₹269.44 करोड़ अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियाँ: 3493	➢ 2012 में शुरू की गई ईएमसी योजना भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों का समर्थन करती है। ➢ अप्रैल 2020 में अधिसूचित ईएमसी 2.0 योजना उपरोक्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसके लिए आवेदन मार्च 2024 तक खुले हैं और मार्च 2028 तक वितरण किया जाएगा। ➢ योजना की प्रगति: योजना के तहत ₹184.91 करोड़ जारी किए गए हैं और इससे ₹40,429 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और 5.02 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)

मोटर वाहन उद्योग

10.25. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में विभिन्न श्रेणियों में प्रमुख वैश्विक ऑटो निर्माता शामिल हैं, साथ ही एक जीवंत ऑटो कंपोनेंट उद्योग भी शामिल है जो विभिन्न ऑटो पार्ट्स, बॉडी और चेसिस का उत्पादन करता है। पिछले पाँच वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 23 के दौरान ऑटोमोटिव पार्ट्स के घरेलू उत्पादन और खपत के मूल्य में वृद्धि कम हुई है। ऑटो कंपोनेंट का उत्पादन घरेलू और निर्यात बाजारों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर ऑटोमोबाइल उत्पादन के रुझानों का बारीकी से अनुसरण करता है। जैसा कि नीचे देखा गया है, महामारी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को काफी प्रभावित किया, जिससे ऑटोमोटिव पार्ट्स की मांग कमजोर हुई और इसलिए, उनके विस्तार की गति कम हुई।

10.26 पिछले दशक की पहली छमाही में, यात्री वाहनों, जैसे कि कारों और उपयोगिता वाहनों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। हालाँकि, महामारी का ऑटोमोटिव उद्योग के सभी क्षेत्रों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। जबकि यात्री वाहनों में जल्दी सुधार हुआ, दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रिकवरी की अवधि लंबी है। चार्ट X.17 से पता चलता है कि कारें और यूटिलिटी वाहन (यूवी), तिपहिया, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन वर्तमान में विस्तार कर रहे हैं, जैसा कि हाल के वर्षों की वृद्धि दरों में देखा गया है। वित्त वर्ष 24 में, देश ने लगभग 49 लाख यात्री वाहन, 9.9 लाख तिपहिया, 214.7 लाख दोपहिया और 10.7 लाख वाणिज्यिक वाहन बनाए।

चार्ट X.16: ऑटोमोटिव पार्ट्स उद्योग का प्रदर्शन

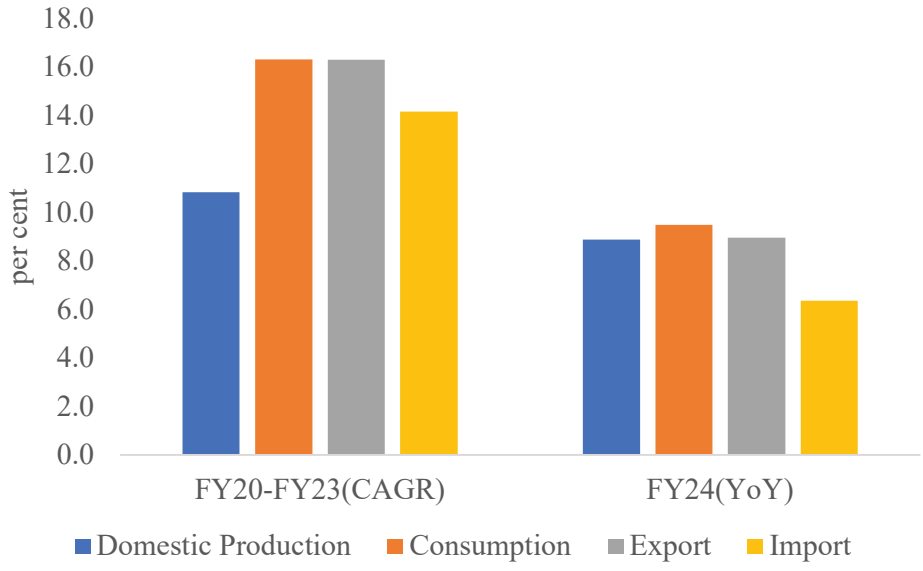

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

चार्ट X.17: विभिन्न श्रेणियों के ऑटोमोबाइल के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)

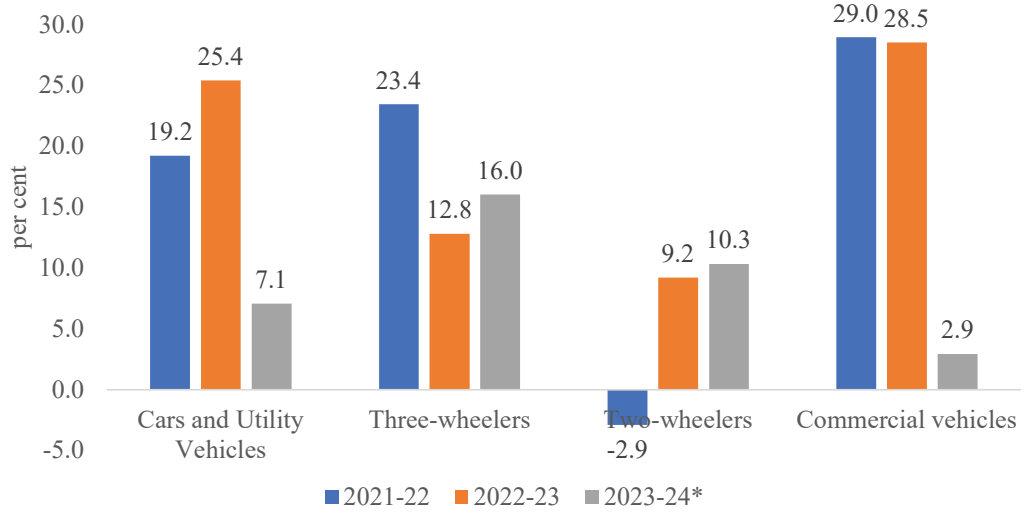

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

बॉक्स X.7: ऑटोमोबाइल और ई-मोबिलिटी के लिए नीतिगत समर्थन

	ई-मोबिलिटी के लिए	
पीएलआई योजना के तहत	**बैटरी भंडारण**	**फेम योजना का चरण II**
• ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना में वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 27 तक ₹25,938 करोड़ का बजटीय परिव्यय है।	• आवेदकों ने 1.48 लाख रोजगार सृजन का प्रस्ताव दिया है, जिसके सापेक्ष 31/03/2024 तक 28,884 रोजगार सृजन हो चुका है।	• सरकार ने 24 जनवरी 2024 को 10 गीगावाट घंटा की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया। 70 गीगावाट घंटा की संचयी क्षमता के लिए बोलियाँ प्राप्त हुई।

- चौंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना और घटक चौंपियन प्रोत्साहन योजना में उप-विभाजित।
- 85 आवेदकों को मंजूरी दी गई है।
- 67,690 करोड़ का प्रस्तावित निवेश आकर्षित किया गया, जिसके लिए मार्च 2024 के अंत तक 14,043 करोड़ का निवेश किया जा चुका है।
- इस योजना को वित्त वर्ष 28 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

- मई 2021 में 18,100 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी।
- गीगा स्केल एसीसी और बैटरी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करके एसीसी की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- एसीसी के लिए 50 गीगावॉट घंटे की संचयी एसीसी विनिर्माण क्षमता और आला एसीसी प्रौद्योगिकियों के लिए 5 गीगावॉट घंटे की संचयी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है।
- एसीसी पीएलआई बोली का पहला दौर मार्च 2022 में संपन्न हुआ, जिसके तहत 30 गीगावॉट घंटे की क्षमता आवंटित की गई।
- सरकार ने 24 जनवरी 2024 को 10 गीगावाट घंटा की कुल विनिर्माण क्षमता के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया। 70 गीगावाट घंटा की संचयी क्षमता के लिए बोलियाँ प्राप्त हुईं।

- वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 के दौरान 5 वर्षों के लिए 11500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत।
- इसका उद्देश्य 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 पहिया वाहनों, 5 से वित्त वर्ष 5000 ई-4 पहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-2 पहिया वाहनों की सहायता से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा करना है। ई-वाहनों में प्रगति तालिका X.2 में प्रस्तुत की गई है।
- भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) को मार्च 2024 में मंजूरी दी गई थी।
- जुलाई 2024 तक 4 महीने की अवधि के लिए ₹500 करोड़ के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024)। इसका उद्देश्य पंजीकृत ई-रिक्शा, ई-कार्ट और एल5 सहित ई2 व्हीलर्स और ई3 व्हीलर्स को तेजी से अपनाना है।

तालिका X.2: फेम योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत प्रोत्साहित वाहनों की संख्या ('000 में)

खंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
e-2W	11.4	29.3	116.6	208.8	804.2	1170.2
e-3W	3.4	9.1	21.8	19.8	76.2	130.3
e-4W	0.7	0.7	0.7	2.1	1.4	16.6
e-bus	0.0	0.4	0.7	1.6	1.9	4.6
Total	15.6	39.6	139.8	232.2	894.6	1321.8

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण गणना

क्रॉस-कटिंग थीम

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

10.27. भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई। मई 2024 तक ₹1.28 लाख करोड़ से अधिक का निवेश दर्ज किया गया, जिससे ₹10.8 लाख करोड़ का उत्पादन/बिक्री हुई और 8.5 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजन हुआ। निर्यात

में ₹4 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

10.28. सरकार ने ₹6,238 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट्स) के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। मई, 2024 तक पीएलआई योजना के तहत व्हाइट गुड्स (एसी, एलईडी) द्वारा प्राप्त संचयी निवेश ₹3181 करोड़ था, जिससे ₹13320 करोड़ की संचयी बिक्री हुई। शेष क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना संबंधित क्षेत्र अनुभागों के अंतर्गत आती है।

चार्ट X.18: पीएलआई योजना के तहत वास्तविक क्षेत्रवार निवेश

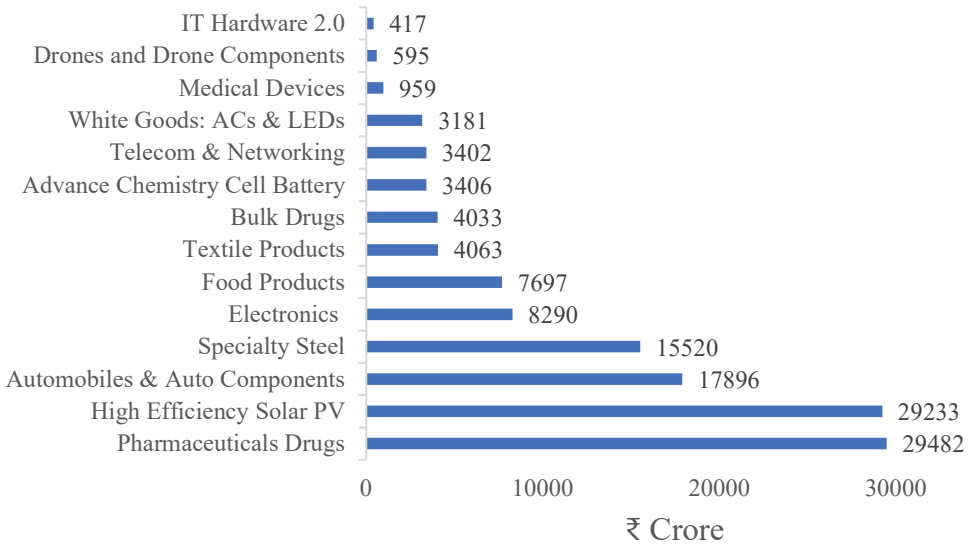

स्रोत: नीति आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

10.29. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई की हिस्सेदारी 35.4 प्रतिशत थी। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के डेटा प्रसार पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2023-24 में अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई-निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 45.7 प्रतिशत थी।

10.30. वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23[20] के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल, 2021-मार्च 2022 की तुलना में अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 की अवधि के दौरान भारत में असंगठित उद्यमों की संख्या में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, प्रति कर्मचारी सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) ₹1,38,207 से बढ़कर ₹1,41,769 हो गया और प्रति प्रतिष्ठान सकल उत्पादन मूल्य (जीवीओ) ₹3,98,304 से बढ़कर ₹4,63,389 हो गया। यह श्रम सहित संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के साथ उत्पादकता में वृद्धि को दर्शाता है, जो निरंतर आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।

10.31. जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया उद्यम पंजीकरण पोर्टल, स्व-घोषणा के आधार पर एक सरल, ऑनलाइन और निःशुल्क पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करके एमएसएमई को औपचारिक बनाने में सहायक रहा है। 05 जुलाई 2024 तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 4.69 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम भी शामिल हैं। उद्यम पंजीकरण एमएसएमई को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने में मदद

20 एमएसएमई गो डिजिटल: कोविड-19 संकट के दौरान बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, आईसीआरआईईआर, 2022, पृष्ठ 10 (MSMEs_Go_Digital.pdf (icrier.org))

करता है। उद्यम-पंजीकृत एमएसएमई बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भी पात्र हैं। उद्यम पोर्टल का 37 अन्य पोर्टलों के साथ एपीआई लिंकेज है और इसके माध्यम से डेटा साझा करने की सुविधा है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है।

10.32. केंद्रीय बजट 2023-24 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) को ₹9,000 करोड़ आवंटित किए गए, जिसका लक्ष्य कम लागत के साथ अतिरिक्त ₹2 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराना है। वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 24 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए गारंटी की राशि और संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई (चार्ट X.19)।

बॉक्स X.8: एमएसएमई ऋण योजनाएं

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	ऋण गारंटी योजना (सीजीएस)
• वित्त वर्ष 23 के दौरान, ₹2,722.17 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 85,167 सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान की गई, जिससे लगभग 6.81 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। • वित्त वर्ष 24 में, यह सहायता ₹3,093.87 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 89,118 सूक्ष्म इकाइयों तक बढ़ा दी गई, जिससे लगभग 7.13 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए।	• सीजीटीएमएसई द्वारा प्रशासित • 85 प्रतिशत तक की गारंटीकृत कवरेज के साथ ₹5 करोड़ तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण की पेशकश करके एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली ऋण बाधाओं को कम करने का लक्ष्य। • इस योजना ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक ₹6.78 लाख करोड़ की राशि की 91.76 लाख गारंटी को मंजूरी दी है। अकेले वित्त वर्ष 24 में, ₹2.03 लाख करोड़ की 17.24 लाख गारंटी को मंजूरी दी गई।

चार्ट X.19: सीजीटीएमएसई के तहत स्वीकृत गारंटियों में काफी वृद्धि हुई

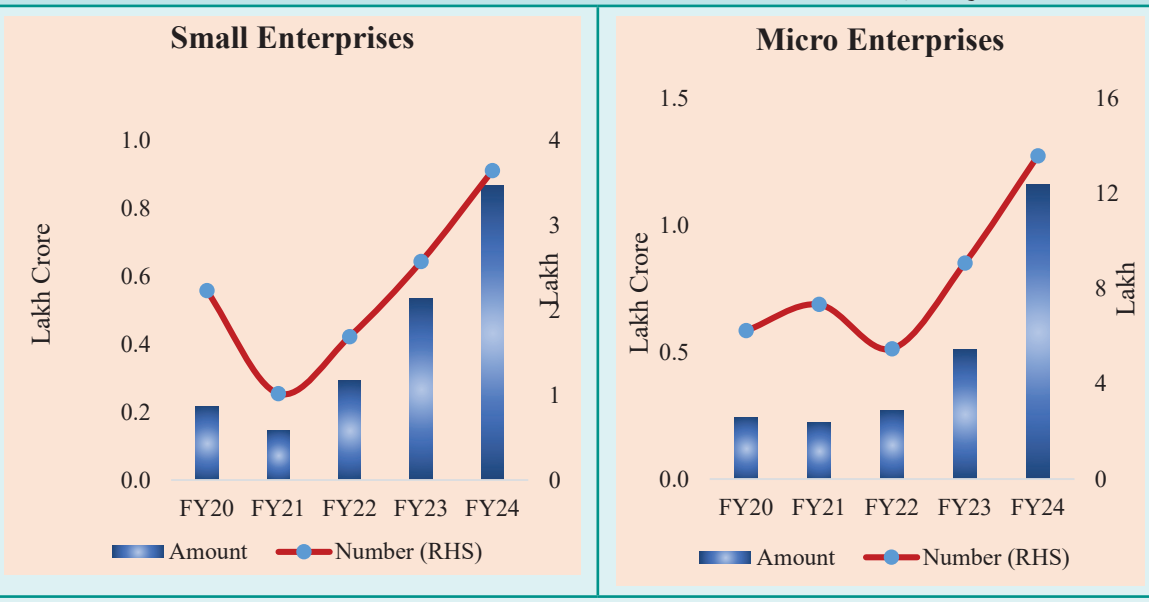

स्रोत: एमएसएमई मंत्रालय

10.33. **चुनौतियाँ और अवसर:** एमएसएमई को औपचारिकता और समावेशन, वित्त, बाजार, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण तक सीमित पहुँच, बुनियादी ढाँचे की अड़चनें और कौशल विकास सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने औपचारिकता, पंजीकरण में आसानी और शिकायत निवारण के लिए

पहल और प्लेटफॉर्म लागू किए हैं, जैसे समाधान पोर्टल, संबंध पोर्टल और चौंपियंस पोर्टल, जो भुगतान में देरी, खरीद की निगरानी और शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायता करते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकास रिपोर्ट (2019) इस बात पर प्रकाश डालती है कि यद्यपि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एसएमई का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था उन्हें महत्वपूर्ण नए अवसर प्रदान करती है। यह भारत के एमएसएमई क्षेत्र में स्पष्ट है, जहाँ 2020-21 में कुल ई-कॉमर्स बिक्री का लगभग 70 प्रतिशत[21] एमएसएमई से था, जो साल-दर-साल 60-70 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। इसके अलावा, शोध से पता चलता है कि फैक्ट्री स्पेस के उपयोग पर विनियमन के स्तर को पुनः परिभाषित करने से, जैसे कि सेटबैक से संबंधित विनियमनों से, विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु फर्मों की (बॉक्स X.9)।

बॉक्स X.9: विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भवन विनियमों की पुनर्कल्पना

मौजूदा औद्योगिक भवन विनियम फैक्ट्री भूमि उपयोग को सीमित करते हैं, भूमि उपयोगिता को कम करते हैं और परिणामस्वरूप अनिर्धारित लागतें होती हैं। विनियमन की स्थितिः नौकरियों और विकास के लिए भवन मानक सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट[22] बताती है कि कैसे भूमि कवरेज, सेटबैक, पार्किंग और फ्लोर एरिया अनुपात से संबंधित चार भवन विनियमों का अनुपालन करते हुए भूमि अप्रयुक्त रहती है।

1. **ग्राउंड कवरेज के कारण भूमि का नुकसानः** रिपोर्ट से पता चलता है कि फैक्ट्री भूखंडों पर ग्राउंड कवरेज नियमों के तहत, घनत्व को नियंत्रित करने और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एक फैक्ट्री की इमारत प्लॉट के 40-60 प्रतिशत से अधिक को कवर नहीं कर सकती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वह किस राज्य में अपने फैक्ट्री का परिचालन करता है। इसकी तुलना में, हांगकांग में, किसी फैक्ट्री के भूखंड का कोई भी हिस्से का नुकसान नहीं होता; फिलीपींस में, भूखंड का केवल 30 प्रतिशत नुकसान होता है।
2. **आग के कारण भूमि का नुकसानः** राज्य-स्तरीय नियम आग के जोखिम को कम करने और वेंटिलेशन और प्रकाश सुनिश्चित करने के लिए क्षैतिज भवन विस्तार को सीमित करते हैं। हालांकि, उपर्युक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि नियम प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रियाओं में आधुनिकीकरण को ध्यान में नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, आग प्रतिरोधी सामग्री और स्वचालित अग्निशमन उपकरणों का उपयोग भूमि को बंद किए बिना खतरों को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। इसके अलावा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ उद्योगों में प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन प्रतिकूल हो सकता है। कुछ राज्यों में सूक्ष्म और लघु कारखानों के लिए आग विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। इन नियमों को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों में कारखानों को अपनी 60-90 प्रतिशत भूमि भी खोनी पड़ती है। भारतीय राज्य में एक मेगा फैक्ट्री फिलीपींस की तुलना में आग के कारण लगभग 2 गुना अधिक भूमि खोती है और सिंगापुर की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक भूमि खोती है।
3. **पार्किंग नियमों के कारण भूमि का नुकसानः** राज्य सरकारें सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग अनिवार्य करने वाले नियम लागू करती हैं। हालाँकि, शोध से पता चलता है कि ये अनिवार्यताएँ वास्तव में और अधिक भीड़भाड़ में योगदान दे सकती हैं। पार्किंग की आवश्यकताएँ वास्तविक माँग के अनुरूप नहीं हैं, जिसके कारण कारखानों को काफी मात्रा में भूमि खोनी पड़ रही है। रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत भर में कारखानों को पार्किंग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी लगभग 12-70 प्रतिशत भूमि खोनी पड़ रही है। भारत में एक कारखाने को हांगकांग, फिलीपींस या सिंगापुर की तुलना में कम से कम दोगुनी संख्या में कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।
4. **फ्लोर रेशियो के कारण भूमि का नुकसानः** राज्य निर्दिष्ट भूमि के भाग पर ऊर्ध्वाधर विस्तार को प्रतिबंधित करने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को विनियमित करते हैं, जिसका उद्देश्य घनत्व का प्रबंधन करना, यातायात की भीड़ को कम करना और पानी और बिजली जैसी आवश्यक उपयोगिताओं के प्रावधान को

21 एमएसएमई गो डिजिटलः कोविड-19 संकट के दौरान बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, आईसीआरआईईआर, 2022, पृष्ठ 10 (MSMEs_Go_Digital.pdf (icrier.org))

22 भुवाना, ए., कौर, एस., और रॉय, एस., दिसंबर 2023। 'विनियमन की स्थितिः नौकरियों और विकास के लिए मानकों में सुधार का निर्माण'। प्रोस्पेरिटी,

सुविधाजनक बनाना है। हालाँकि, ऐसे नियम अनजाने में शहरी फैलाव में योगदान दे सकते हैं, जिससे सड़क की भीड़ बढ़ जाती है और उपयोगिता के प्रावधान का खर्च बढ़ जाता है। औसतन, राज्यों में कारखानों को प्लॉट के आकार से 1.3 गुना तक ही फ्लोर स्पेस बनाने की अनुमति है। 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट के साथ, मुंबई में एक कार्यालय भवन 5000 वर्ग मीटर तक बनाया जा सकता है, जबकि जापान में यह 13,000 वर्ग मीटर और सिंगापुर और हांगकांग में 15,000 वर्ग मीटर तक बनाया जा सकता है।

विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए भवन विनियमों की जांच करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। भूमि के बेहतर उपयोग से प्रति इकाई उत्पादन की निश्चित लागत आएगी, जिससे उद्यमी को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के अलावा, अंतर-राज्यीय तुलना राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उचित नीतियां अपनाने में मदद कर सकती है।

बॉक्स X.10: ओडीओपी: क्षेत्रीय गौरव और आर्थिक सशक्तिकरण का निर्माण

वर्ष 2018 में, सरकार ने क्षेत्रीय आर्थिक विभाजन को पाटने और भारत के विविध जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में उत्पादित एक एकल, प्रतिष्ठित उत्पाद के माध्यम से प्रत्येक जिले की विशिष्ट शक्तियों की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार करने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल शुरू की। जिन जिलों में एक से अधिक उत्पादों की पहचान की गई है, उन्हें द्वितीयक या तृतीयक उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये उत्पाद कृषि, विनिर्माण, हथकरघा और वस्त्र, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। इस पहल ने अब तक देश भर के 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की है।

ओडीओपी पहल को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 24 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी, जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए अपने राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक "यूनिटी मॉल" स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इन "पीएम-एकता मॉल" का उद्देश्य ओडीओपी के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है। ये मॉल देश के अनूठे उत्पादों के लिए एक जीवंत बाजार बना रहे हैं, जिसका लक्ष्य घरेलू और विदेशी दोनों बाजार हैं।

सरकार ओडीओपी को बढ़ावा देने और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए कई पहल कर रही है। केंद्र और स्थानीय विक्रेताओं के बीच सहयोग को सुगम बनाने और स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 15 राज्यों में 'ओडीओपी संपर्क' कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान देश भर में आयोजित विभिन्न जी20 कार्यक्रमों में ओडीओपी ने दुनिया के सामने भारत को प्रदर्शित किया, जहाँ कार्यक्रमों के दौरान कारीगरों, विक्रेताओं और बुनकरों को वैश्विक मंच पर काफी पहचान मिली।[23]

ओडीओपी की कुछ सफलता की कहानियाँ

- विभिन्न सरकारी पहलों द्वारा वित्तपोषित पैक शेड और सिंचाई के परिणामस्वरूप कश्मीर के शोपियां में सेब के उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- उत्तरकाशी जिले में गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय प्रशासन और 700 से अधिक किसानों को 15 विशेष प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से जैविक खेती के कौशल से सशक्त बनाया गया है। 1000 से अधिक लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों से सुसज्जित, इस जिले में लाल चावल का उत्पादन काफी बढ़ गया है।
- आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में लगभग 1,50,000 आदिवासी परिवारों ने गिरिजन सहकारी निगम के ऋणों से कॉफी उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है।

23 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2000801

- ओडिशा के कंधमाल जिले में 5,000 से अधिक प्रशिक्षित श्रमिकों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हल्दी बाजारों को आकर्षित करने के लिए 1,300 किसानों के साथ मिलकर काम किया है। मसाले की सरकारी खरीद में भी लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पंजाब के भटिंडा जिले में त्वरित परीक्षण प्रयोगशालाओं, सब्सिडी, ऋण के रूप में वित्तीय सहायता और औपचारिकीकरण के लिए समर्थन के कारण शहद उत्पादन[24] में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)

10.34. 31 मार्च, 2023 तक 254 सीपीएसई प्रचालन में थे। लगभग 66 प्रतिशत सीपीएसई सेवा क्षेत्र में संचालित थे; बाकी विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन तथा खनन और अन्वेषण में। सीपीएसई ने वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में मजबूत वित्तीय मापदंड हासिल किए। भारत के स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले 63 सीपीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 31 मार्च, 2023 तक ₹16.69 लाख करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 तक यह ₹15.46 लाख करोड़ था, जो 7.95[25] प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 23 में परिचालन करने वाले सीपीएसई का कुल निवल लाभ ₹2.12 लाख करोड़ था। सीपीएसई के प्रमुख वित्तीय मापदंड नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

चार्ट X.20: वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 23 के बीच सीपीएसई के प्रदर्शन में सुधार (सीएजीआर)

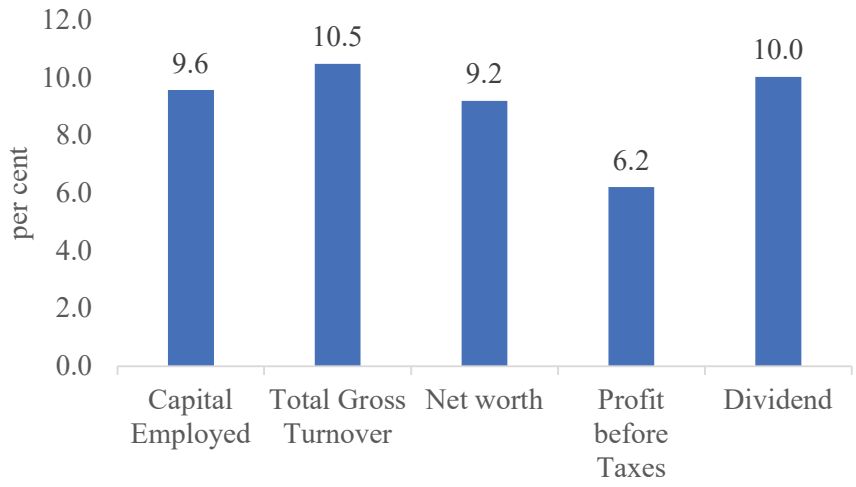

स्रोत: पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट, लोक उद्यम विभाग

चार्ट X.21: लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या में सुधार हुआ है

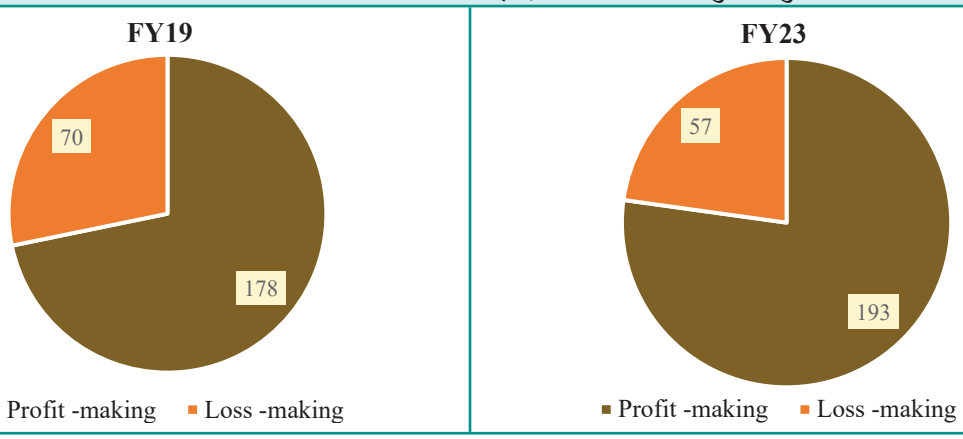

स्रोत: पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट, लोक उद्यम विभाग

24 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 2 फरवरी 2024 की पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, लिंक यहां उपलब्ध है: https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151807-ModuleId%20=%202

25 https://dpe.gov.in/sites/default/files/PES%202022-23_E.pdf

औद्योगिक ऋण

10.35. औद्योगिक ऋण वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आर्थिक गतिविधि की चक्रीयता, बैंक फंड और अन्य बाजार विकल्पों की उपलब्धता और लागत में सापेक्षता, औद्योगिक उद्यमों के अपने संसाधनों की स्थिति और बैंकिंग प्रणाली की अपनी जोखिम क्षमता शामिल है। वित्त वर्ष 21 में महामारी के कारण मंदी से उबरते हुए, अगले वर्ष औद्योगिक ऋण में जोरदार वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 23 में, ऋण वृद्धि मुख्य रूप से बड़े उद्योगों द्वारा संचालित थी; हालाँकि, कुछ क्षेत्रों को ऋण में कमी के कारण यह वृद्धि बाधित हुई।

चार्ट X.22: उद्योग में सकल बैंक ऋण के परिनियोजन में वृद्धि

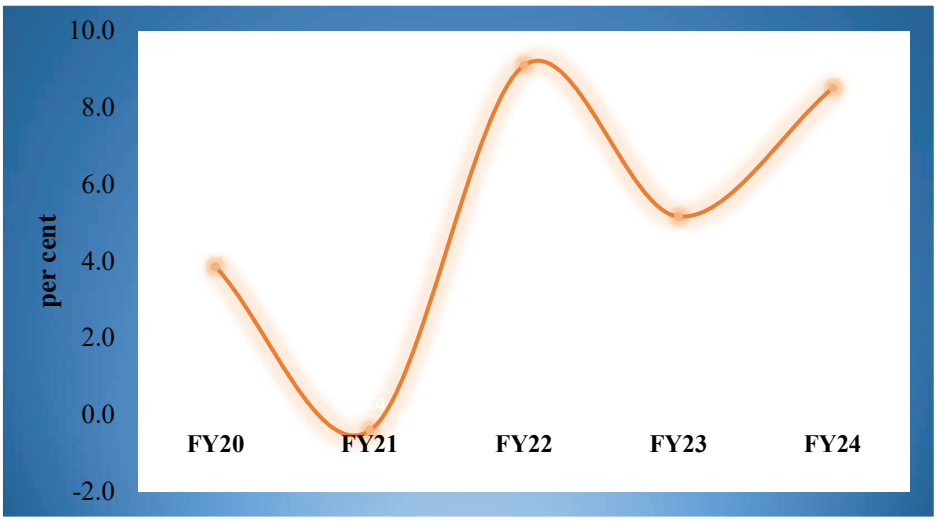

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, सकल बैंक ऋण की उद्योगवार परिनियोजन, आरबीआई
नोट 1: मार्च 2019 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा एक संशोधित प्रारूप पर आधारित है, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मूल्यों और विकास दरों में बदलाव आया है।
नोट 2: मार्च 2022 के लिए चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए क्रेडिट डेटा समायोजित किया जाता है।
नोट 3: 2023-24 के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

तालिका X.3: ऋण परिनियोजन में उद्योग-वार वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)

न्यूनतम	कम → अधिकतम	
	मार्च 2020 से मार्च 2024 तक सीएजीआर	मार्च-24 में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)
खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	4.5	-10.1
खाद्य प्रसंस्करण	9.7	14.9
पेय पदार्थ और तम्बाकू	14.6	30.9
वस्त्र	7.3	11.2
चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	4.7	5.4
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	15.0	12.4
कागज और कागज के उत्पाद	9.2	4.9
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	13.4	-11.4
रसायन और रासायनिक उत्पाद	5.8	11.3
रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	14.5	7.6
कांच और कांच के बने पदार्थ	15.4	26.3

सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-0.5	2.9
मूल धातु और धातु उत्पाद	3.5	12.2
सभी इंजीनियरिंग	4.8	10.5
वाहन, पुर्जे और परिवहन उपकरण	5.9	11.4
रत्न और आभूषण	6.2	8.0
निर्माण	1.1	6.9
बुनियादी ढांचा	4.7	6.6
अन्य उद्योग	3.7	18.4
कुल उद्योग	5.5	8.5

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस, सकल बैंक ऋण की उद्योगवार परिनियोजन, आरबीआई

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार

10.36. चूंकि मुख्य विनिर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति केवल लगभग 7 प्रतिशत तक सीमित है, इसलिए औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में भी इसकी हिस्सेदारी सीमित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2023 संकेतक की प्रारंभिक समीक्षा से पता चलता है कि कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास में अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद चीन और जर्मनी का स्थान है। भारत, तुर्की, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे मध्यम आय वाले देशों ने भी अपने अनुसंधान एवं विकास[26] में वृद्धि का अनुभव किया है। चूंकि भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित है, इसलिए शीर्ष पांच क्षेत्रों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका X.4: भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथ्य: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21 औसत

भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास व्यय (करोड़ रुपये)	44720
विनिर्माण GVA के प्रतिशत के रूप में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास	1.61
निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास, निजी क्षेत्र के विनिर्माण GVA के प्रतिशत के रूप में	1.53
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण GVA के प्रतिशत के रूप में	2.67
औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या: निजी क्षेत्र	1866
औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या: सार्वजनिक क्षेत्र	94

चार्ट X.23: भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास व्यय में उप-क्षेत्रों की हिस्सेदारी: वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21

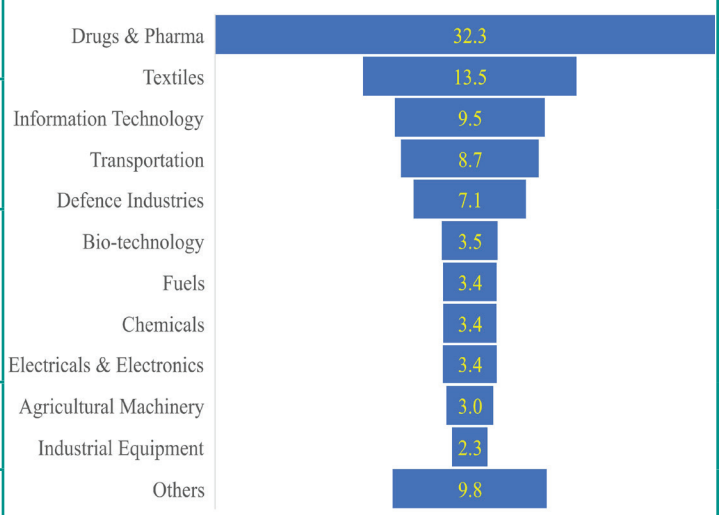

स्रोत: अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

26 वैश्विक नवाचार सूचकांक (2023) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

10.37. समावेशी, टिकाऊ और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक समग्र नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। नवाचार प्रणाली हितधारकों और संस्थानों के बीच प्रणालीगत बातचीत पर जोर देती है जो नवाचार प्रक्रियाओं[27] को प्रभावित करती है। इसमें अनौपचारिक और जमीनी स्तर के नवाचार से अंतर्दृष्टि शामिल है, जो विशिष्ट मांगों को पूरा करने की उनकी क्षमता को उजागर करती है। भारत में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं:

बॉक्स X.11: भारत में स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास

पेटेंट और अनुसंधान	स्टार्ट-अप्स	प्रतिस्पर्धा
• पेटेंट नियम, 2024 को अधिसूचित किया गया, जिससे पेटेंट अधिग्रहण और प्रबंधन सरल हो गया। • स्वीकृत पेटेंट की संख्या 2014-15 में 5978 से सत्रह गुना बढ़कर 2023-24 में 103057 हो गई। • पंजीकृत डिजाइन 2014-15 में 7147 से बढ़कर 2023-24 में 30672 हो गए। • अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) विधेयक 2023 पारित किया गया। 2023-28 के दौरान इसकी अनुमानित लागत ₹50,000 करोड़ है। • एएनआरएफ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह उद्योग, शिक्षा, सरकारों और अनुसंधान निकायों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और इंटरफेस की सुविधा प्रदान करेगा।	• 2016 में लगभग 300 स्टार्ट-अप से, मार्च 2024 के अंत तक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या बढ़कर 1.25 लाख से अधिक हो गई। • मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में से 45 प्रतिशत से अधिक टियर 2/3 शहरों से उभर रहे हैं। • मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में से 47 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। • स्टार्ट-अप ने 2016 से जनवरी 2024 तक 13,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दायर किए। वित्त वर्ष 24 के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में 13,000 से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं। • स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स के तहत, 135 से अधिक वैकल्पिक निवेश फंडों को 10,500 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता जताई गई है, जिन्होंने वित्त वर्ष 24 के अंत तक स्टार्ट-अप में 18,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। • भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध हितधारकों को एक साथ लाना है।	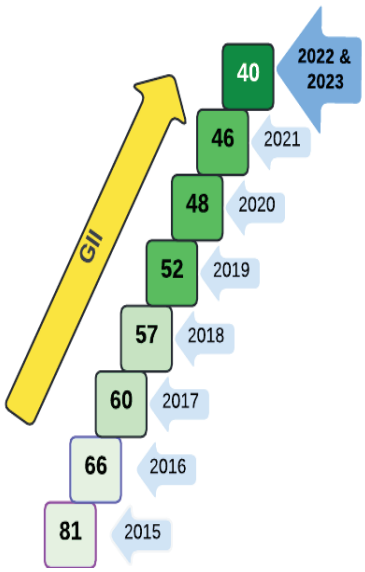 • ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के तहत भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। • भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों और मध्य और दक्षिणी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। • भारत घरेलू बाजार पैमाने के संकेतक में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर है।

स्रोत: डीपीआईआईटी

27 लुंडवैल, बी. ए., जोसेफ, के. जे., चौमिनेड, सी., वांग, जे. (2009)। 'नवाचार प्रणाली और विकासशील देशों की पुस्तिका' चेल्टेनहैम: एडवर्ड एल्गार्ड

निष्कर्ष एवं दृष्टिकोण

10.38. उपर्युक्त विश्लेषण भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में उभरते रुझानों का संकेत देता है। सबसे पहले, पिछले दशक में, औद्योगिक खंडों के बीच उत्पादन हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। रसायन, लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, परिवहन उपकरण, इस्पात और मशीनरी और उपकरण जैसे क्षेत्रों में मजबूती आई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक मध्यवर्ती और उपभोक्ता सामान हैं, जबकि अन्य पूंजी निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरी ओर, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ और तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पाद और चमड़ा जैसे क्षेत्रों ने अपनी सापेक्ष स्थिति खो दी है।

10.39 दूसरे, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न औद्योगिक खंडों का निर्यात-आयात संतुलन काफी हद तक अलग-अलग रहा है। लगातार, प्रमुख शुद्ध निर्यातकों में इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग शामिल हैं। दूसरी ओर, कोयला, पूंजीगत सामान और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयात निर्भरता जारी है।

10.40 तीसरा, पूंजीगत वस्तुओं और इस्पात तथा सीमेंट जैसे प्रमुख निर्माण इनपुट की मांग पर मध्यम अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक रहने की संभावना है, क्योंकि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण गति पकड़ रहा है। वैश्विक अनिश्चितताएं कोयला, पेट्रोलियम, इस्पात और मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण आयातित इनपुट पर निर्भरता के कारण निर्यात मांग और उत्पादन की घरेलू लागत पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

10.41 सरकार ने व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने और लॉजिस्टिक तथा अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कई पहल की हैं। प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, उत्पादन, बिक्री और निर्यात को बढ़ावा दिया है और रोजगार पैदा किए हैं, विशेष रूप से सफेद वस्तुओं के मामले में। देश भर की सरकारें जहाँ मदद कर सकती हैं, वह है उन नियमों की समीक्षा, संशोधन, शिथिलता और निरस्तीकरण करना जो अव्यवस्थित, खराब, अनुत्पादक हैं और बिना किसी लोक हित के व्यवसायों के संचालन की लागत बढ़ाते हैं। उद्यमियों के लिए सबसे अच्छे निर्णय कानून द्वारा अनिवार्य हैं, जिससे अभियोजन का डर पैदा होता है। भारत में आगे के औद्योगीकरण का मार्ग विनियमन से प्रशस्त होता है।

10.42 उद्योगों में दो सामान्य आवश्यकताएँ अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने और कार्यबल के कौशल स्तरों में सुधार लाने से संबंधित हैं। दोनों के संबंध में, उद्योग को नेतृत्व करना चाहिए। किसी भी वित्तीय प्रोत्साहन के बगैर, अनुसंधान एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता उद्योग के डीएनए में होनी चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता के बारे में है। उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सक्रिय सहयोग और पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने के साथ, भारत अब तक की तुलना में कौशल की कमी को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है।

10.43 कपड़ा जैसे व्यापक रूप से बिखरी उत्पादन इकाइयों वाले क्षेत्र और सामान्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बाजार पहुंच और औपचारिकता की बाधाओं के समाधान की तलाश में हैं। एमएसएमई के भाग में उल्लिखित इन मुद्दों को हल करने के लिए कई केंद्रित नीतिगत पहल की गई हैं; सहकारी संघवाद मोड में उपयुक्त सरकारों के स्तर पर निम्नलिखित दिशा में आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है:

(क) एमएसएमई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सहायता प्रणाली सुनिश्चित करना और ऐसी परियोजनाओं के लिए उनकी बैंकिंग क्षमता और पर्याप्त वित्तपोषण व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(ख) रोजगार-प्रधान एमएसएमई खंडों के लिए लक्षित सुविधा और प्रोत्साहन।

(ग) मंजूरी के लिए एकल-खिड़की तंत्र के साथ अनुपालन आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर आसान बनाना, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और एमएसएमई को इन प्रक्रियाओं को आसानी से संभालने के लिए सुसज्जित करना।

(घ) एमएसएमई उत्पादों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर की सुविधा प्रदान करना।

(ङ) कार्यबल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार-उद्योग-अकादमिक सहयोग।

10.44 निम्नलिखित आधार पर उद्योग के आंकड़ों को उन्नत करने से नीति निर्माण में सहायता मिलेगी:

(क) औद्योगिक उत्पादन का अद्यतन सूचकांक, जिसमें भारत के विनिर्माण परिदृश्य में हुए व्यापक बदलावों को शामिल किया गया है। ऐसे सूचकांकों के राज्य स्तरीय रूपांतर उभरते भौगोलिक पैटर्न को समझने में मदद करेंगे।

(ख) एमएसएमई में उत्पादन और रोजगार की गतिशीलता के नियमित संकेतक।

(ग) उद्योग-वार बैंक ऋण के सकल संवितरण (वर्तमान में उपलब्ध बकाया ऋण के आंकड़ों के विपरीत) की जानकारी, घरेलू और बाहरी इक्विटी और ऋण मार्गों के साथ-साथ अन्य वित्तपोषण स्रोतों के माध्यम से उद्योग-वार मासिक सकल वित्तीय प्रवाह।

****